(b) if so, the details thereof; and

(c) the extent to which the joint military exercises would strengthen our power?

THE MINISTER OF DEFENCE (SHRI GEORGE FERNANDES): (a) Yes, Sir.

(b) No dates have been finalised as yet for conducting Indo-French joint military exercises. The second meeting of the Indo-French High Committee on Defence Cooperation is expected to be held during 1999.

(c) Conduct of military exercises between the armed forces of India and friendly foreign countries provides an opportunity to the Indian armed forces to gain an insight into the operations and doctrines of the armed forces of the other countries. These also enhance tactical awareness and provide the Indian armed forces an exposure to the systems, equipment, thinking and procedures prevalent in the armed forces of the other countries.

सामाजिक असमानता के कारण जनसंहार

*220. **श्री जनेश्वर मिश्र:** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि देश के विभिन्न भागों में सामाजिक असमानता और भेदभाव इस स्तर तक पहुंच गया है कि बिहार, आन्ध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश में समाज गृह युद्ध की ओर अग्रसर होता हुआ प्रतीत होता है;

(ख) क्या यह भी सच है कि प्राय: इसकी समाप्ति जनसंहार से होती है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस प्रकार की सामाजिक असमानता और भेदभाव को दूर करने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

गृह मंत्री (श्री लाल कृष्ण आडवाणी): (क) से (ग) विभिन्न सामाजिक-आर्थिक और राजनैतिक कारणों से, बिहार, आन्ध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और उड़ीसा के हिस्सों में अल्ट्रा लेफ्ट ग्रुप्स के सशस्त्र दस्ते सक्रिय हैं। तथापि, किसी भी राज्य में सिविल-वार जैसी स्थिति नहीं है।

सामाजिक असमानता इत्यादि को दूर करने के लिए सरकार द्वारा उपाय करना, एक सतत् प्रक्रिया है। इस दिशा में, राज्य सरकारों से समय-समय पर, प्रभावित क्षेत्रों का बेहतर सामाजिक-आर्थिक विकास सुनिश्चित करने और संसक्तिशील कार्य योजना के आधार पर इस समस्या का मुकाबला करने के लिए विविध क्षेत्रों जैसे कि लोक शिकायतों का निवारण, बेहतर अभिगमन के लिए समुचित सड़क व्यवस्था, रोजगार सृजन कार्यक्रमों पर जोर देना, पंचायती राज प्रणाली को मजबूत करना, समुचित भूमि सुधार, आदिवासियों के भूमि की बहाली करना ग्रामीण ऋणग्रस्तता को हटाना तथा विकास कार्यक्रमों को स्थानीय आवश्यकताओं के अनुसार तैयार करना, इत्यादि जैसे उपाय करने का अनुरोध किया गया है।

केन्द्रीय गृह मंत्री ने वामपंथी उग्रवादी गतिविधियों की पुनरीक्षा करने के लिए 15.6.1998 को आन्ध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उड़ीसा के मुख्य मंत्रियों की हैदराबाद में एक बैठक की थी। इस बैठक में लिए गए निर्णयों पर की गई अनुवर्ती कार्रवाई के फलस्वरूप केन्द्रीय गृह सचिव की अध्यक्षता में इन चार राज्यों के मुख्य सचिवों और पुलिस महानिदेशकों को सदस्य के रूप में लेकर गृह मंत्रालय ने एक समन्वय केन्द्र की स्थापना की है। बाद में, बिहार को भी समन्वय केन्द्र के सदस्य के रूप में शामिल कर लिया गया। इस समन्वय केन्द्र ने अपनी तीन बैठकें 19.7.1998, 12.10.1998 और 4.1.1999 को की है। इन बैठकों में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णयों में यह है कि प्रभावित क्षेत्रों का समेकित विकास करने के लिए राज्यों को कार्य योजना तैयार करनी चाहिए तथा उन्हें गृह मंत्रालय को भेजना चाहिए जो इस प्रयोजनार्थ अलग से धन निर्धारित करने के लिए उन्हें आगे योजना आयोग को भेजेगा। आन्ध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और उड़ीसा से प्राप्त कार्य योजना को, तद्नुसार योजना आयोग को भेज दिया गया है।

WRITTEN ANSWERS TO UNSTARRED QUESTIONS

राज्य बिजली बोर्डों को कोयले की आपूर्ति

1551. **श्री चीमनभाई हरीभाई शुक्ला:** क्या कोयला मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राज्य बिजली बोर्ड और कोयला मंत्रालय के बीच कोयला आपूर्ति के संबंध में चल रहे विवाद के कारण विद्युत उत्पादन पर अत्यधिक प्रभाव पड़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने उक्त विवाद में हस्तक्षेप किया है;

(ग) क्या राज्य बिजली बोर्ड द्वारा कोयला मंत्रालय को देय राशि का भुगतान न करने के कारण कोयला आपूर्ति को स्थगित करने के आदेश जारी करने के कोई प्रयास किये जा रहे हैं; और

(घ) इस स्थिति से निपटने के लिए अब तक क्या उपाय किए गए हैं?